73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री जी का संबोधन

सितम्बर 29, 2018

नमस्कार,

माननीय अध्यक्ष महोदया,

सबसे पहले, मैं आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के73वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने जाने पर, अपनी ओर से तथा अपने देश भारत की ओर से, बहुत बहुत बधाई देती हूँ।एक महिला होने के नाते, व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिए यह गर्व की बात है।

यह चुनाव मुझे यह भी याद दिलाता है कि संयुक्त राष्ट्र को पहली महिला अध्यक्ष देने का गौरव, भारत को ही प्राप्त हुआ है,जब वर्ष 1953 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ के आठवें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई थीं।

अध्यक्ष जी, मैं 72वें सत्र का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए निवर्तमान अध्यक्ष श्री लाइजैक के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ।

अध्यक्ष जी, आज सुबह बहुत अशुभ समाचार मिला। इंडोनेशिया में भूकंप और सूनामी - दोनों त्रासदी एक साथ आयी है। मैं आज इस मंच से, मेरे देश भारत की ओर से, इंडोनेशिया की सरकार और वहाँ के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ ; और इसके साथ ही इस त्रासदी का मुक़ाबला करने के लिए भारत की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी देती हूँ ।

अध्यक्ष जी,

संयुक्त राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मंच है।

1. जहाँ दुनिया के सुखः दुख साँझे किए जाते हैं।

2. जहाँ अविकसित तथा कम विकसित देशों की सहायता के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं।

3. जहाँ विश्व को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 में हमने वर्ष 2030 का एजेन्डा निर्धारित करते हुएटिकाऊ विकास के लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की रचना की थी। उसी समय से यह कहा जा रहा है यदि भारत इन लक्ष्यों कोप्राप्त करेगा, तभी हम सफ़ल हो पायेंगे वरना हम फ़ेल हो जायेंगे।

अध्यक्ष जी,

आज इस मंच से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारत आपको कभी फ़ेल नहीं होने देगा। वर्ष 2030 के एजेंडा तथा टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस गति और जिस पैमाने पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य शुरु किया है, हम समयावधि से पहले ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे।

इस संबंध में भारत में किए जा रहे कार्यों की एक झलक के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक समावेश की योजना चलाई गई है- जन-धन-योजना, जिसके अन्तर्गत 32 करोड़ 61 लाख ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं, जिन्होंने पहले कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था।

Direct Benefit Transfer (DBT) योजना के माध्यम से सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली राशि, सीधे उन खातों में डाली जा रही है।जिसके कारण गरीब को पूरा पैसा मिलने लगा है तथा बीच का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है।

इसी तरह भारत में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई है- आयुष्मान भारत योजना।पिछले सप्ताह ही 23 तारीख़ को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है।इस योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की राशि उनकी बीमारी के इलाज के लिए दी जाएगी।

स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के क्षेत्र मेंयह योजना क्रांतिकारी साबित होगी।अध्यक्ष जी, जब हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है –'सर्वे सन्तु निरामयाः' यानि सब निरोगी हों।यह योजना उस कामना की पूर्ति करेगी।

इसी तरह बेघरों को घर देने के लिए विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना चलाई गई है- प्रधानमंत्री आवास योजना।इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख आवास शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में बनाये जायेंगे ताकि 2022 तक हर ग़रीब के पास अपना घर हो, कोई भी बेघर ना रहे।

अभी तक 53 लाख 50 हज़ार मकान बनाये जा चुके हैं। इसी तरह बेरोज़गार लोगों को स्वरोजगारी तथा उद्यमी बनाने की दिशा में कौशल विकास योजना के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देकर तथा मुद्रा योजना के माध्यम से काम शुरु करने के लिए ऋण देकर,दो प्रभावी योजनायें चलाई जा रही हैं।यहाँ मैं विशेष रूप से यह उल्लेख करना चाहूँगी कि मुद्रा योजना के अन्तर्गत 14 करोड़ 9 लाख लोगों को ऋण दिया गया है।जिसका 76% केवल महिलाओं को दिया गया है।प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि यदि ग़रीबी का उन्मूलन करना है तो सबसे पहले महिलाओं का सशक्तिकरण करना होगा।

मैंने जितनी योजनाओं का उल्लेख किया है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है और कुछ अन्य योजनायें केवल महिलाओं को ही लाभ देने के लिए चलाई जा रही हैं जैसे उज्ज्वला योजना, मातृत्व अवकाश योजना। पिछली बार इसी मंच से मैंने उज्ज्वला योजना के विषय में उल्लेख किया था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त गैस सिलेंडर प्रदान किया जा चुका है।

मातृत्व अवकाश योजना यानि Maternity Benefit Scheme के अन्तर्गत भारत में कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशु को देखभाल के लिए 26 हफ़्तों की छुट्टी वेतन सहित दी जाती है।अध्यक्ष जी, एक महिला होने के नाते आप इस योजना से महिलाओं को मिलने वाले लाभ को आसानी से समझ सकती हैं।

हम सबको जानकारी है कि कुछ विकसित देशों में वेतन सहित 6 हफ़्तों की छुट्टी प्राप्त करने के लिए महिलाएं संघर्ष कर रही हैं लेकिन भारत ने वेतन सहित 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लागू कर दिया है। अध्यक्ष महोदया, सन् 2022 में आज़ाद भारत 75 वर्ष का हो जाएगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया है।वो भारत होगा-

1. स्वच्छ भारत—स्वस्थ भारत

2. समर्थ भारत—समृद्ध भारत

3. सुरक्षित भारत—विकसित भारत और

4. ऊर्जावान भारत—शक्तिमान भारत

हम बहुत तेज गति से इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वर्ष 2022 तक यह संकल्प, सिद्धि में बदल जाये,इसका पुरज़ोर प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी,

विश्व आज जिन चुनौतियों से जूझ रहा है,उसमें जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं।जलवायु परिवर्तन की चुनौती के सबसे बुरे परिणाम अविकसित और कम विकसित देश भोग रहे हैं और उनमें अपने बचाव की ना सामर्थ्य है, ना क्षमता। इसलिए जिन विकसित देशों ने प्रकृति का विनाश करके अपना विकास किया है,वो आज अपनी जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकते।यदि हम विश्व को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचाना चाहते हैं तो बड़े देशों को, छोटे देशों की सहायता के लिए आगे आना ही होगा।

पेरिस समझौते में Common but Differentiate Responsibility with Respective Capabilities के सिद्धांत को दोहराते हुए इसी सत्य को स्वीकार किया गया है। इसीलिए विकसित देशों को छोटे देशों के लिए राशि भी देनी चाहिए और तकनीक भी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए पेरिस समझौते के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ़्राँस के साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी।अब इस गठबंधन में 68 देशों ने सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इसी वर्ष 11 मार्च को हमने फ़्राँस के राष्ट्रपति मैक्रों की सह-अध्यक्षता में इस गठबंधन का स्थापना सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 120 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र नेप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए Champions of the Earth Award से सम्मानित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी जी तो "One Sun - One Grid" की संकल्पना भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि हम सबका सूर्य एक है, तो Grid भी एक ही क्यों ना हो जाए,यदि यह संकल्पना पूरी हो गई, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आ जायेगी, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक प्रभावी माध्यम बनेगी।

अध्यक्ष जी,

मैंने दूसरी प्रमुख चुनौती कही थी – आतंकवाद।20वीं शताब्दी की समाप्ति के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी में शांति और समृद्धि का युग प्रारम्भ होगा।किन्तु 9/11 की न्यूयॉर्क की घटना और 26/11 की मुम्बई की घटना ने इन उम्मीदों पर पानी फ़ेर दिया।

आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से,तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुँचा है।भारत तो कई दशकों से इसका दंश भोग रहा है।और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमापार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना।अमेरिका के इतिहास में 11 सितम्बर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है।

इसीलिए उस घटना के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन कोअमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था औरपूरी दुनिया में उसे खोज रहा था लेकिनउसे नहीं मालूम था कि ख़ुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहाँ पनाह देकर उसे छिपा रखा था।

यह तो अमेरिका के खुफ़िया तंत्र की सफलता है कि उन्होंने ओसामा को वहाँ खोज निकाला और यह अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है किउन्होंने उसे वहीं मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिये,सारा सच सामने आ जाने के बाद भीना चेहरे पर

झेंप ना माथे पर शिकन।ऐसे बर्ताव किया जैसे कोई गुनाह किया ही ना हो।और यह सिलसिला अभी भी थमा नहीं है, लगातार जारी है।

9/11 वाला मास्टर माइंड तो मारा गया किन्तु 26/11 का मास्टर माइंड हाफ़िज सईद आज भी खुला घूम रहा है। रैलियाँ करता है, चुनाव लड़वाता है,सरे आम भारत को धमकियाँ देता है।लेकिन यह संतोष की बात है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है और इसीलिए FATF ने आतंकवादियों की आर्थिक सहायता करने के लिए (Terror Funding के लिए) उसे निगरानी सूची में रख दिया है।

अध्यक्ष जी,

हम पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं होते।यह पूरी तरह असत्य है। हमारा तो मानना है कि दुनिया के जटिल से जटिल मुद्दे केवल बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं और सुलझाये जाने चाहियें।

इसीलिए पाकिस्तान के साथ अनेक बार वार्ता शुरु की गई है।वार्ताओं के अनेक दौर चले हैं, लेकिन हर बार उनके ही कारण वार्ता रोकनी पड़ी है। अध्यक्ष जी, भारत में अनेक राजनैतिक दलों की सरकार केन्द्र में बनी है, हर सरकार ने यह कोशिश की, कि बातचीत के द्वारा हमारे विवाद सुलझ जायें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के सभी नेताओं को आमंत्रित करके सरकार बनने से पहले ही यह शुरुआत कर दी थी।

9 दिसंबर 2016 को स्वयं मैंने इस्ला माबाद जाकर Comprehensive Bilateral Dialogue की शुरुआत की थी किन्तु मात्र तीन हफ्ते के बाद 2 जनवरी की रात को पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया गया।अध्यक्ष जी, आप ही बतायें,उस माहौल में बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती थी। अभी भी पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद वहाँ के

प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह इच्छा जताई कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो जाए तो अच्छा है।

हमने उनका प्रस्ताव मंज़ूर किया लेकिन चन्द घंटों बाद ही यह ख़बर आई कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का अपहरण करके उन्हें मारकर फेंक दिया।क्या यह हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं, और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है, या होनी चाहिए? आए दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है।अध्यक्ष जी, मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तो आतंकवादी करते हैं, जो निर्दोष लोगों को मारते हैं,बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारते हैं,लेकिन पाकिस्तान पैरवी करता है मारने वालों की और जो मारे जाते हैं, उन पर चुप्पी साध लेता है।

भारत के खिलाफ़ दुष्प्रचार करना, ग़लत तस्वीरें दिखाकर मानवाधिकार के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाना, पाकिस्तान की आदत बन गई है।यह घटना इसी सभागार में घटी थी, पिछले वर्ष ही घटी थी,जब पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने Right to Reply काउपयोग करते हुए अपने उत्तर में एक दूसरे देश की तस्वीर दिखाकर भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया था।

अध्यक्ष महोदया,

पिछले पाँच वर्षों से लगातार इस मंच से भारत कहता आ रहा है कि केवल एक सूची या दूसरी सूची मेंआतंकवादियों या उन्हें शह देने वालों का नाम रख देने से हम आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।जब तक हम उन्हें किसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की गिरफ़्त में नहीं लायेंगे, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा।

भारत ने 1996 में CCIT का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था।आज तक वह प्रस्ताव अटका हुआ है और अटकने का केवल एक कारण है कि हम आतंकवादी की परिभाषा पर

सर्वसम्मति नहीं बना पा रहे।यह विडंबना है कि हम आतंकवाद से लड़ना भी चाहते हैं लेकिन आतंकवादी कौन है, इसे परिभाषित भी नहीं कर पा रहे।

उस बुराई से हम कैसे लड़ेंगे,जिसकी परिभाषा हम तय नहीं कर सकते।इसीलिए विश्व के इनामी आतंकवादी पाकिस्तान मेंस्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं और उन आतंकवादियों की क्रूरता, वीरता कही जाती है।पाकिस्तान की सरकार उनके सम्मान में डाक टिकटें निकालकर उन्हें महिमामंडित करती है।

अध्यक्ष जी, ऐसे कृत्यों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कब तकचुप बैठकर देखते रहेंगे। ऐसी करतूतों की कब तक अनदेखी करते रहेंगे।यदि इन हरकतों को कानून बनाकर अभी नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आतंकवाद का यह दानव पूरी दुनिया को निगल जाएगा और इस दावानल में पूरा विश्व जल जाएगा। इसलिए आज मैं पुनः आपसे अपील करती हूँ कि आतंकवाद की परिभाषा पर सर्व सम्मति बनाकर जल्दी से जल्दी CCIT को हम पारित करें।

अध्यक्ष जी, अब मैं संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र, दुनिया के देशों का सबसे बड़ा मंच है लेकिन अब मैं एक वाक्य इसके आगे और जोड़ना चाहती हूँ कि धीरे धीरे इस मंच का महत्व, इसका प्रभाव, इसकी गरिमा और इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। हमें इस बात की चिन्ता करनी चाहिए कि इस क्षरण के चलते कहीं हमारा हश्र भी League of Nations जैसा ना हो जाये।

लीग का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वह सुधार के लिए तैयार नहीं हुआ। हम वो ग़लती ना करें।संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता है और उसमें भी सबसे पहले सुरक्षा परिषद् के सुधार जरूरी हैं।और सुधार केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि ऐसे सुधार जो दिल और

दिमाग में बदलाव लायें।आज सुरक्षा परिषद दूसरे विश्व युद्ध के पाँच विजेताओं तक ही सीमित है क्या इसे आज के युग के अनुकूल माना जा सकता है?

जब भारत समेत विश्व का अधिकांश हिस्सा उपनिवेशवाद की गिरफ़्त में था, उस समय की बनाई हुई सुरक्षा परिषद क्या आज के विश्व की चुनौतियों को समझ पा रही है?मुकाबला करना तो दूर, वो चुनौतियाँ भी उसकी समझ से परे हैं इसलिए मेरी अपील है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया शीघ्र शुरु की जानी चाहिए।

अध्यक्ष जी,

इस सत्र में Multilateralism यानि बहुपक्षीय व्यवस्था के विषय में बहुत चर्चा हो रही है। क्योंकि इस व्यवस्था के सामने जो चुनौतियाँ खड़ी की जा रही हैं, उससे सभी देश चिन्तित हैं।मैं भी इस विषय में अपनी ओर से भारत का मत रखना चाहूँगी।

अध्यक्ष महोदया,

भारत वसुधैव कुटुंबकम् के सिद्धांत में विश्वास रखता है,इसलिए Multilateralism को कमजोर करने का समर्थन कभी नहीं करेगा।

वसुधैव कुटुंबकम् की बुनियाद है परिवार और परिवार प्यार से चलता है , व्यापार से नहीं परिवार मोह से चलता है, लोभ से नहीं परिवार संवेदना से चलता है, ईर्ष्या से नहीं परिवार सुलह से चलता है, कलह से नहीं इसीलिए हमें संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत पर चलाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र, मैं, मेरा और मुझको कहकर नहीं चलाया जा सकता। यह मंच, हम — हमारा और सबको के सिद्धांत पर बनाया गया था। उसी आधार पर चलेगा तो जीवित रहेगा।

भारत नहीं चाहता कि इस मंच से कुछ देशों के ही हित साधने के लिए निर्णय लिए जायें या कुछ देशों का अहित करने की दृष्टि से ही निर्णय लिए जायें।हमें सबका सहयोग लेकर सबके विकास के लिए निर्णय लेने होंगे।

अध्यक्ष जी,

इस वर्ष भारत महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगाँठ मनाने की शुरुआत कर रहा है।गांधी जी का प्रिय भजन था-"वैष्णव जन तो तेने कहिएजो पीड़ पराई जाणे रेपर दुःखे उपकार करे तोयेमन अभिमान ना आणे रे”

इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर महसूस करता है, वही अच्छा इन्सान है और जो दूसरे के दुःख का निवारण करता है लेकिन मन में अभिमान की भावना नहीं लाता, वही अच्छा इन्सान है।

अध्यक्ष जी,

इस मंच को हमें वैष्णव-जन का मंच बनाना है,जो मंच अविकसित देशों की पीड़ा को समझे, और विकसित देशों के माध्यम से उनकी पीड़ा को कम करने का कार्य करे।अभिमान की भावना से नहीं,पीड़ितों के कल्याण की भावना से काम करे।अहंकार की भावना से नहीं उपकार की भावना से काम करे।

तभी हम ऐसे विश्व की रचना कर पायेंगे जिसमें सद्भाव हो, सौहार्द हो, शान्ति हो, प्यार हो और जो विश्व हिंसा से मुक्त हो, आतंकवाद से मुक्त हो और तनाव से भी मुक्त हो। ऐसे विश्व की कामना करते हुए संस्कृत के एक श्लोक के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगी।

सर्वेशां स्वस्तिर भवतु
सर्वेशां शांति भवतु
सर्वेशां पूर्णम भवतु
सर्वेशां मंगलं भवतु

इसका अर्थ है-

सबका शुभ हो
सबको शांति मिले
सबको पूर्णता प्राप्त हो
सबका मंगल हो
सबका कल्याण हो

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।

न्यूयॉर्क
29 सितंबर 2018